केजरीवाल अब अपने को करें निर्दोष साबित

आर.के. सिन्हा

कौन नहीं जानता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता पर आते ही अराजकता फैलने लगी। हद तो तब हो गई जब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की मुख्यमंत्री ने अपने निजी सहायकों द्वारा सरकारी आवास पर मध्य रात्रि में बुलवाकर गुंडे किस्म के हिस्ट्रीशीटर विधायकों द्वारा लात- घूंसों से पिटाई करवा दी। ऐसा शर्मनाक वाकया पहले कभी नहीं सुना था कि मुख्यमंत्री के आवास पर किसी आला आई.ए.एस अफसर को सत्तासीन दल के विधायकों द्वारा लात-घूंसों से पीटा जाए। यदि कोई सरकार ही गुंडई पर उतारू हो जाये तो उससे भी तो फिर उसकी भाषा में ही तो निबटना होता है।

प्र अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की शराब नीति के जिन आरोपों के आधार पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है, उन्हें साबित होना भर ही बाकी है। हां, पर इतना तो कहना ही होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल अपने को बार-बार अराजक मुख्यमंत्री के रूप में साबित करने में सफल रहे। वे लगातार केन्द्र सरकार और सरकारी अफसरों से लड़ने-झगड़ने के मूड में ही रहे। उन्होंने एक तरह से मान लिया कि देशभर में वह ही अकेले ईमानदार है। बाकी दुनिया भ्रष्ट है। उनसे उम्मीद थी कि वह देश में साफ-सुथरी और वैकल्पिक राजनीति का रास्ता साफ करेंगे। पर उन्होंने अपने खोखले दावों-वादों और कारनामों से देश को निराश ही किया।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पहले भी सरकारें और मुख्यमंत्री रहे,पर कभी कोई ऐसा मसला नहीं आया। दिल्ली की चुनी हुई सरकारों और केन्द्र सरकारों के बीच मजे-मजे में विकास के सब काम होते रहे। पर सन 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हंगामा शुरू हो गया और होने लगा रोज का क्लेश, तकरार और आरोप-प्रत्यारोप का दौर । दिल्ली में 1951-52 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश बने। चौधरी साहब 1952 से 1955 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें कांग्रेस ने हटाया और यहां का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह मुसाफिर को।

गुस्ताखी माफ, कम ही दिल्लीवालों को पता है कि दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री एक सिख सज्जन थे। वे पहली दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे। वे 13 फरवरी, 1955 से 31 अक्टूबर, 1956 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। मुसाफिर जी ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने नहीं दीं। अजीब इत्तेफाक है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने में सदैव अति उत्साह दिखाते रहे। उन्हें दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के कारण ही गिरफ्तार किया गया है। मुसाफिर जी के पुत्र एस. निहाल सिंह प्रख्यात पत्रकार थे। वे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संपादक भी रहे।

बहरहाल, 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद मिली। यह विधानसभा के समकक्ष थी। महानगर परिषद का मुखिया कार्यकारी पार्षद होता था। इस पद पर विजय कुमार

मल्होत्रा और जगप्रवेश चंद्र जैसे नेता भी रहे। दिल्ली को 1991 में फिर से संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नए परिसीमन के तहत विधानसभा का 1993 में चुनाव हुआ। उसके बाद मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसे दिग्गज नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान केन्द्र में कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाली और कभी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें काम करती रहीं। पर दिल्ली में विकास का पहिया कभी थमा नहीं। जब मदन लाल खुराना मंख्यमंत्री बने तब देश के प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिंह राव थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई । जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तब भी दिल्ली का भरपूर विकास हो रहा था। कहीं कोई विवाद ही नहीं था। सारे विवाद आपसी बातचीत से हल हो रहे थे।

अटल जी और शीला दीक्षित ने दिल्ली में मेट्रो रेल का विस्तार और बिजली की समस्या का स्थायी समाधान किया। यह बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे कि दिल्ली में बिजली की 24 घंटे सप्लाई उनकी वजह से मुमकिन हुई। हालांकि, उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि दिल्ली में पेयजल संकट का वह हल क्यों नहीं कर सके। क्यों यमुना मैली ही होती रही? कैसे दिल्ली बन गई दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी? अरविंद केजरीवाल ने इन सवालों के जवाब देने की कभी जरूरत महसूस नहीं की। अरविंद केजरीवाल को यही लगता रहा कि अखबारों में बड़े-बड़े खचीर्ले विज्ञापन देकर वे अपने को महान साबित करते रहेंगे।

आप जब दिल्ली में जी.टी.रोड से आगे बढ़ते हैं, तो आपको दूर से ही भलस्वा में काला पहाड़ नजर आने लगता है। वह दिन में भी डराता है। अगर उसे पहली बार देखेंगे तो लगेगा कि मानो कोई प्राचीन किला हो। पर यह कूड़े का ढेर है। इस तरह के कूड़े के पहाड़ राजधानी में गाजीपुर तथा ओखला में भी है। भलस्वा, ओखला और गाजीपुर के इन पहाड़ों में कुछ औरत-मर्द कुछ बीनते हुए नजर आ जाते हैं। जिस राजधानी दिल्ली में हरी-भरी लुटियंस दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली छावनी और दर्जनों अन्य शानदार एरिया हैं, वहां लगभग सौ एकड़ एरिया में फैले कूड़े के किले शर्मसार करते हैं।

यह तीनों कूड़े के किले अरविंद केजरीवाल के तमाम दावों की कलई खोल कर रख देते हैं। इनके आसपास बेबस लोग रहते हैं। क्या कभी अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि किस तरह से इनके पास लोग नारकीय स्थिति में रहते होंगे? इनसे हर वक्त भयंकर दुर्गंध आती रहती है। अब तो दिल्ली विधानसभा और नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। पर यह कूडे के किले पहले की तरह से खड़े हैं या यह कहिये कि प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं। यह कहना होगा कि दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के निस्तारण और इसकी री-साइक्लिंग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। क्या इन काले पहाड़ों को हटाने से मोदी सरकार ने मना किया था?

राजधानी के एक एक बड़े भाग में लुटियंस दिल्ली आती है। इसमें केन्द्रीय मंत्री, सांसद, बड़े उद्योगपति वगैरह रहते हैं। इसके रखरखाव पर मोटा बजट खर्च होता है। राजधानी के नई दिल्ली एरिया की देखभाल नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) करती है। यहां पर तो कमोबेश सब कुछ ठीक है। इसकी तुलना दुनिया के किसी भी शहर के हिस्से से की जा सकती है। इधर कोई कूड़े के पहाड़ भी नहीं हैं। मसला शेष दिल्ली का है। उसका हल भी मुमकिन है अगर कूड़े की-साइक्लिंग को लेकर रफ्तार से काम चले।

कौन नहीं जानता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता पर आते ही अराजकता फैलने लगी। हद तो तब हो गई जब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की मुख्यमंत्री ने अपने निजी सहायकों द्वारा सरकारी आवास पर मध्य रात्रि में बुलवाकर गुंडे किस्म के हिस्ट्रीशीटर विधायकों द्वारा लात- घूंसों से पिटाई करवा दी। ऐसा शर्मनाक वाकया पहले कभी नहीं सुना था कि मुख्यमंत्री के आवास पर किसी आला आई.ए.एस अफसर को सत्तासीन दल के विधायकों द्वारा लात-घूंसों से पीटा जाए। यदि कोई सरकार ही गुंडई पर उतारू हो जाये तो उससे भी तो फिर उसकी भाषा में ही तो निबटना होता है। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को अपने को पाक-साफ करना होगा।

(लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

संपादकीय

पुष्कर सिंह धामी सरकार के निराशाजनक 2 साल!

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा की माने तो इन दो वर्षों के कार्यकाल में राज्य की धामी सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, जिस पर राज्यवासियों को गर्व हो सके। उनका मानना है कि भाजपा सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में केवल महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों का उत्पीड़न करने, जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने तथा मंहगाई, भ्रष्टाचार व बरोजगारी बढ़ाने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया है,जिसपर गर्व किया जा सके।हम आंकलन करे तो भाजपा सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड में हत्या, चोरी, डकैती, मासूमों से बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।जिनमे अंकिता भण्डारी जघन्य हत्याकाण्ड, हेमा नेगी हत्याकाण्ड, पिंकी हत्याकाण्ड, जगदीश चन्द हत्याकाण्ड, विजय वात्सल्य हत्याकाण्ड, केदार भण्डारी तथा विपिन रावत हत्याकाण्ड जहां शामिल है।वही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग से बलात्कार की घटना से गिरती कानून व्यवस्था उजागर हो गई है,जो राज्य की अस्मिता पर चोट भी है।साथ ही राज्य सरकार के कई विभागों में हुए भर्ती घोटालों और व्याप्त भ्रष्टाचार से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार इन दो वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही है और उसका भयमुक्त समाज -भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा ध्वस्त होकर रह गया है। चाहे वह अंकिता भण्डारी हत्याकांड हो, हेमा नेगी हत्याकांड हो, पिंकी हत्याकांड, जगदीश चन्द हत्याकांड, विजय वात्सल्य हत्याकाण्ड, केदार भण्डारी तथा विपिन रावत हत्याकाण्ड हो,इन सारे जघन्य हत्याकाण्डों में सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप भी विपक्ष द्वारा लगाए जाते रहे है। वही चर्चित अंकिता भण्डारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम धामी सरकार अभी तक उजागर नहीं कर पाई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला, लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, फारेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटालो में हुई कई गिरफ्तारियां जिनमें अधिकतर भाजपा नेता संलिप्त थे ,से भाजपा सरकार का चेहरा उजागर हुआ है।जिसके चलते राज्य की धामी सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के आरोपो से घिरती रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एस.राजू द्वारा अपने त्यागपत्र में आरोपित घोटाले मे लिप्त सफेदपोश नेता कौन है ,इस पर भाजपा सरकार आज तक मौन साधे हुए है। भर्ती घोटालों में आरोपित हाकम सिंह सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी है और हरिद्वार के संजय धारीवाल तथा नितिन चौहान मण्डल अध्यक्ष व महामंत्री हैं इससे स्पष्ट है कि दो साल के कार्यकाल में सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार का उद्योग बड़ी तेजी से फलता-फूलता रहा है।

चिंतन-मनन

हनुमान से सीखें संस्कार

दूसरे का मान रखते हुए हम सम्मान अर्जित कर लें, इसमें गहरी समझ की जरूरत है। होता यह है कि जब हम अपनी सफलता, सम्मान या प्रतिष्ठा की यात्रा पर होते हैं, उस समय हम इसके बीच में आने वाले हर व्यक्ति को अपना शत्रु ही मानते हैं। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मनुष्य सारे संबंध दांव पर लगा देता है। आज के युग में महत्वाकांक्षी व्यक्ति का न कोई मित्र होता है, न कोई शत्रु। उसे तो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी होती है। हर संबंध उसके लिए शस्त्र की तरह हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरे की भावनाओं, रिश्ते की गरिमा और सबके मान-सम्मान को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा पर चलते हैं। हनुमानजी उनमें से एक हैं। सुंदरकांड में एक प्रसंग है। हनुमानजी और मेघनाद का युद्ध हो रहा था। मेघनाद बार-बार हनुमानजी पर प्रहार कर रहा था, लेकिन उसका नियंत्रण बन नहीं रहा था। तब उसने हनुमानजी पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। हनुमानजी को भी वरदान था कि वह किसी अस्त्र-शस्त्र से पराजित नहीं होंगे। उनका नाम बजरंगी इसीलिए है कि वे वज्रांग हैं। जिसे कह सकते हैं स्टील बॉडी।

जैसे ही शस्त्र चला, हनुमानजी ने विचार किया और तुलसीदासजी ने लिखा-

ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा कपि मन कीन्ह बिचार।
जौं न ब्रह्मासर मानउं महिमा मिटइ अपार।।

अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब हनुमानजी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। यहां हनुमानजी ने अपने पराप्रम का ध्यान न रखते हुए, ब्रह्मजी के मान को टिकाया। दूसरों का सम्मान बचाते हुए अपना कार्य करना कोई हनुमानजी से सीखें।

भारत का सियासी दारोमदार मध्यम वर्ग के कंधों पर

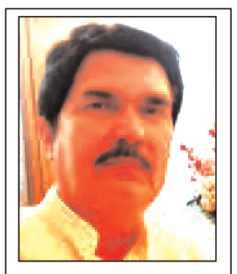

डॉ हिदायत अहमद खान

इंडियन इकोनॉमी को हाई जम्प कराने में मध्यम वर्ग का योगदान किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता है। अब जबकि दुनिया अत्याधुनिक काल में प्रवेश कर चुकी है तो मिडिल क्लास की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके चलते भारतीय मध्य वर्ग पर विदेशी इकोनॉमिस्ट भी नजरें जमाए हुए हैं। खास बात यह है कि विदेशी रणनीतिकार भी नीति बनाते समय इन पर फोकस करना नहीं भूलते हैं। इसे देखते हुए ही कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 पिछले चुनावों की तरह जाति और धर्म पर केंद्रित न होकर मिडिल क्लास पर केंद्रित होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। वैसे भी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा-पत्रों से मिडिल क्लास को ज्यादा उम्मीद नहीं होती है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने और सरकार में आने के बाद वही वादे चुनावी जुमलेबाजी में तब्दील हो जाते हैं। मध्यम वर्ग के पाले में तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद संघर्ष ही आता है। इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि मध्य वर्ग की ताकत घटी है या संख्याबल में कमी आई है, बल्कि महज वोट बैंक के तौर पर ही नहीं बल्कि हर मामले में मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ रही है। पिछले दिनों प्राइस आईसीआई की जारी रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि भारत की कुल जनसंख्या का 31 फीसदी तो मध्यम वर्ग के दायरे में आने वाली जनता ही है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2047 तक यही आंकड़ा बढ़कर 60 फीसदी तक पहुंच जाएगा। बात साफ है कि आने वाले समय में भारत की आधी से अधिक आबादी मिडिल क्लास की होने जा रही है। बावजूद इसके मिडिल क्लास संगठित नहीं होने के कारण हर जगह हाशिये पर पटक दिया जा रहा है। सरकारें भी योजनाएं और रणनीति बनाते समय या तो अत्यंत गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर बनाती हैं या फिर वो चंद पूंजीपति उनकी नजर में होते हैं, जिनसे पग-पग में उनका वास्ता पड़ता है। मिडिल क्लास सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब से खुश या दुःखी होता हुआ देखाई देता है, इससे ज्यादा की उसकी मानों कोई एहमीयत भी नहीं है। सर्वे करने वाले तो दावा कर रहे हैं कि जब हमारे हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो देश में मिडिल क्लास की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। इस आंकड़े से कंपनियां खासी खुश हो सकती हैं, क्योंकि उनके लिए तो मिडिल क्लास एक बड़ा मार्केट है, जिसे भुनाने में वो अपनी ताकत लगा देंगी, लेकिन इसमें उनका अपना लाभ ज्यादा होगा, जबकि मिडिल क्लास को मिडिल में ही रखने की भी भरसक कोशिशें होंगी, क्योंकि जो इससे ऊपर निकल गया फिर वह न तो कंपनी के काम का रह जाता है और न ही धुर राजनीति करने वालों के ही काम का। इसलिए सभी की कोशिशें तो यही होती हैं कि मिडिल क्लास को बनाया रखा जाए, ताकि कम लागत पर ज्यादा उत्पादन करने की स्ट्रजी को आसानी से लागू किया जा सके। चाहे एफएमसीजी कंपनियों की बात हो या कोई और सेक्टर वालों की सभी को मिडिल क्लास की ताकत का पता होता है, लेकिन खुद इस वर्ग को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता वर्ना वो भी अपनी शक्ति पर गुमान करने लग जाएं और हर वो बात सरकार व कंपनियों से मनवा लें जो उनके अपने हक व लाभ के लिए जरुरी होती हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मिडिल क्लास में एका नहीं है, किसी बात को उठाने और सरकार व कंपनियों के सामने रखने के लिए जिस एकजुटता की आवश्यकता होती है वह भी इनमें कतई नहीं होती है, जिसका फायदा गाहे-बगाहे सभी उठाते रहते हैं।

फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मिडिल क्लास की बातें हो रहीं हैं, लेकिन वो भी सियासी हाशिये पर रखकर। यह अलग बात है कि चुनावी झंडा उठाने से लेकर चुनाव कैंम्पैन करने तक मध्यम वर्गीय परिवार का किशोर व जवान ही सबसे आगे नजर आता है। अमीर तो सिर्फ आदेश देने और व्यवस्था देखने के लिए होता है, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए मध्यम वर्ग ही होता है, जो कि मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है। ऐसे में इस चुनाव में होना तो यह चाहिए था कि मध्यम वर्ग की चिंता करते हुए उन्हें केंद्र में रखते हुए चुनावी घोषणा-पत्र बनाए जाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वो कारक जरुरी होते हैं जिनका प्रभाव समाज में होता है। ऐसे में सबसे बेहतर परिणाम देने वाला कारक मिडिल क्लास अपने महत्व को जब तक प्रतिपादित नहीं कर देता, तब तक हाशिये पर बना रहना उसकी किस्मत में है। इसके लिए सियासी रणनीति और बराबर की हिस्सेदारी पर ध्यान देने और कार्य करने की आवश्यकता है, जिस दिन इस पर कार्य होने लगेगा, मिडिल क्लास भी हाशिये पर नहीं रह जाएगा।

आतंकवाद से निपटना आज की आवश्कता

यू शुक्रवार 22मार्च 24को मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल में लड़ाकू वर्दी पहने 5 बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई और 145 लोग बुरी तरह घायल हो गए. समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राजधानी के पश्चिमी छोर पर स्थित क्रोकस सिटी हॉल में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। बाद में विस्फोट की आवाजें भी सुनाई दीं और कॉन्सर्ट हॉल आग की लपटों में घिरा दिखा। हमलावर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर मौजूद हैं इसकी जिम्मेवारी आई एस आई एस-के ने ली हैइस्लामिक स्टेट खुरासान (आईएसआईएस-के) , जिसका नाम उस क्षेत्र के लिए पुराने शब्द पर रखा गया है जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं, 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा और तेजी से अत्यधिक क्रूरता के लिए विख्यात हुआ।इस क्रूरता की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म या कोई नियम कानून नहीं होता वो केवल अपनी माँगों को पूरा करने के लिये सरकार के ऊपर दबाव बनाने के साथ ही आतंक को हर जगह फैलाने के लिये निर्दोष लोगों के समूह या समाज पर हमला करते हैं। उनकी माँगे बेहद खास होती हो, जो वो चाहते हैं केवल उसी को पूरा कराते हैं। ये मानव जाति के लिये एक बड़ा खतरा है। वो कभी-भी अपने दोस्त, परिवार, बच्चे, महिला या बूढ़े लोगों के लिये समझौता नहीं करते हैं। वो केवल लोगों की भीड़ पर बम गिराना चाहते हैं। वो लोगों पर गोलियाँ चलाते हैं, विमानों का अपहरण करते हैं और दूसरी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं।कम से कम समय में अपने मुख्य क्षेत्रों या देशों में आतंक फैलाने के लिये आतंकवादी लक्ष्य बनाते हैं। पूर्व में, ऐसा माना जाता है कि आतंकवादी गतिविधियाँ केवल जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित थी लेकिन अब ये अपनी जड़ें देश के दूसरे क्षेत्रों में भी फैला रहा है। देश में अलग-अलग नामों के साथ कई सारे आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। अपने कार्य के अनुसार राजनीतिक और आपराधिक आतंकवाद के दो मुख्य प्रकार हैं। कुछ खास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित लोगों का समूह है आतंकवाद। विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये एक से ज्यादा आतंकी समूह प्रशिक्षित किये जाते हैं। ये एक बीमारी की तरह है जो नियमित तौर पर फैल रही है और अब इसके लिये कुछ असरदार उपचार की जरुरत है।आतंकवादी कहे जाने वाले प्रशिक्षित लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। वहाँ केवल एक मालिक होता है जो समूह को किसी भी खास कार्य को किसी भी तरीके से करने का सख्त आदेश देता है। अपने अन्यायी विचारों की पूर्ति के लिये उन्हें पैसा, ताकत और प्रचार की जरुरत होती है। ऐसी परिस्थिति में, ये मीडिया होती है जो किसी भी राष्ट्र के समाज में आतंकवाद के बारे में खबर फैलाने में वास्तव में मदद करती है। अपनी योजना, विचार और लक्ष्य के बारे में लोगों तक पहुँच बनाने के लिये आतंकवाद भी मीडिया का सहारा लेता है।अपने उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार विभिन्न आतंकी समूह का नाम पड़ता है। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है और लोगों को इतना डरा देती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। वो सोचते हैं कि आतंक हर जगह है जैसे घर के बाहर रेलवे स्टेशन, मंदिर, सामाजिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि में जाने से घबराते हैं। लोगों के दिमाग पर राज करने के साथ ही अपने कुकृत्यों कों प्रचारित और प्रसारित करने के लिये अधिक जनसंख्या के खास क्षेत्रों के तहत आतंकवादी अपने आतंक को फैलाना चाहते हैं। आतंकवाद के कुछ हालिया उदाहरण 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास का हमला,अमेरिका का 9/11 और भारत का 26/11 हमला है। इसने इंसानों के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुँचायी है।युद्ध द्वारा किसी राष्ट्र से आतंकवाद और आतंक के प्रभाव को खत्म करने के लिये, सरकार के आदेश पर कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। वो सभी जगह जो किसी भी वजह से भीड़-भाड़ वाली जगह होती या बन जाती है जैसे सामाजिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मंदिर आदि को मजबूत सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। सभी को सुरक्षा नियमों का पालन करता पड़ता है और ऑटोमैटिक बॉडी स्कैनर मशीन से गुजरना पड़ता है। इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करने के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को आतंकवादी की मौजूदगी का पता लगाने में मदद मिलती है। इस तरह की कड़ी सुरक्षा प्रबंधन के बाद भी हम लोग अभी-भी आतंकवाद का खिलाफ प्रभावशाली रुप से नहीं खड़े हो पा रहें हैं, उससे लड़ने की आवश्यकता है,आतंकी समूह को खत्म करने के साथ ही आतंक के खिलाफ लड़ने के लिये हर साल हमारा देश ढ़ेर सारे पैसे खर्च करता है। हालाँकि, ये अभी-भी एक बीमारी की तरह बढ़ रही है क्योंकि रोजाना नये आतंकवादी तैयार हो रहें हैं। वो हमारी तरह ही बहुत सामान्य लोग हैं लेकिन उन्हें अन्याय करने के लिये तैयार किया जाता है और अपने एक समाज, परिवार और देश के खिलाफ लड़ने के लिये दबाव बनाया जाता है। वो इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि उन्हें अपने जीवन से भी प्यार नहीं होता, वो लड़ते समय हमेशा अपना कुर्बान होने के लिये तैयार रहते हैं। एक भारतीय नागरिक के रुप में, आतंकवाद को रोकने के लिये हम सभी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और ये तभी रुकेगा जब हम कुछ बुरे और परेशान लोगों की लालच भरी बातों में कभी नहीं आयेंगे।आज, आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को डराने-धमकाने के लिये हो रहा है। बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिज्ञ और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है।

- संजय गोस्वामी